17 39 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

NEW SYSTEM OF STEEL DISTRIBUTION

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है या देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जहा आयरन-ओर होता हो, लाइम-स्टोन होता हो, मैंगनीज होता हो, श्रम हो, सब कुछ हो, वहा हिन्दुस्तान मे सारे ससार के मुकाबले 1 प्रतिशत स्टील पैदा होता है। जापान जैसा मुल्क आज 93 मिलियन टन स्टील अपने यहा पर पैदा करता है, जब कि 1948 मे वही जापान 1 7 मिलियन टन पैदा करता था और हिन्दुस्तान मे केवल 5 6 मिलियन टन स्टील पैदा होता है। आयरनओर और दूसरी सारी चीजे होने के बावजूद भी यह हालात है। लेकिन मै इस बात को इस समय नही कहना चाहता—आज जापान 93 मिलियन टन पैदा करता है, हम उस को आयरन-ओर एक्सपोर्ट करते है और हमारे देश की जो डिमाड है—6 6 मिलियन टन की उसकी भी हम पूर्ति नही कर सकते केवल 5. 6 मिलियन टन ही उपलब्ध करा सके है यह बडे दुख की बात है। मालवीय जी, यह ठीक है कि आप बहुत सारे मिनि-स्टील-प्लांट्स लगाने की योजना बना रहे हैं, आप के दिल मे इस के लिए दर्द है—इस वक्त वास्तव मे मुझे दूसरे विषय पर बोलना है इस लिए मैं इस मे नही जाना चाहता इस समय मुझे केवल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे मे बोलना है मैं समझता हु कि मैं इस समय डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा डिटेल मे न जा कर इतना ही निवेदन करना चाहता हू कि सब मे पहले आप ने 1 मई, 1970 को डिस्ट्रीब्यूशन की एक योजना बनाई थी। आपने सारी स्टेट्स मे जो इन्डस्ट्री-वाइज कोटा फिक्स होता था उसको समाप्त कर दिया उसके बाद आपने उस चीज को फिर से चालू कर दिया। उसके बाद आपने अपने दूसरे नियम बनाये और स्टडी ग्रुप्स मुकर्रर कर दिए। डिपार्टमेन्टल स्टडी ग्रुप्स ने नवम्बर, 1972 मे रिपोर्ट दी। 1972 के बाद फिर आपने एक नयी कमेटी बना दी नवम्बर 1973 मे। मार्च, 1974 मे फिर आपने एक नयी बात सोचनी शुरु कर दी। तो इस तरह से बराबर आपकी कमेटीज बनती गई। 1971 मे स्टडी ग्रुप बिठाये और इंडेंटिंग प्रोसीजर को आपने रखा। फिर 1974 मे नयी बात की। आपने स्पासरिंग अथारिटी के जरिए डाइरेक्ट उनको दिलाने की कोशिश की। आप मुझे क्षमा करेंगे आपने अपनी नयी नीति पैदा कर दी और कहा कि हम इसमे कुछ सुधार करना चाहते है। लेकिन आज आपके स्टील के एलोकेशन और अलाटमेन्ट से कितने ही लोग जो इन्डस्ट्री चलाने नही लेकिन वे मालदार हो गए। उन्होने केवल स्टील का बोर्ड लगा लिया लेकिन किया कुछ भी नही। उन्होने कुछ भी स्टील का प्रोडक्शन नही किया और दूसरी तरफ जो बिलेट्स की मिलें है वह बन्द पडी हैं। इसलिए सवाल यह पैदा होता है देश के सामने सामने कि हिन्दुस्तान मे सभी कुछ चीजे होते हुए भी आज स्टील की यह हालत क्यो है? स्टील का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह गलत क्यो है? आपने प्रापर्टी कमेटीज बना दी, ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटीज बना दी जिनका इतना लम्बा चौडा प्रोसिजर है। आपने रिजनल कन्ट्रोलर भी रख दिये लेकिन इसका क्या असर हुआ मुझे मालूम नही। आपकी इतनी सारी कमेटीज बिठाने के बाद और इतनी स्कीमो के बाद आज भी स्टील का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नही हो रहा है। इसमे बहुत बडा घपला है आज हिन्दुस्तान मे स्टील ब्लैक-मार्केट मे मिलती है। बाम्बे मे स्टेट बैंक की बिल्डिंग बनती है तो उनके पास हजारो टन स्टील पडा हुआ है। यह स्टील कहा से आता है? मालवीय जी जोकि इतने जागरुक हैं, उनके रहते ब्लैक-मार्केट मे यह स्टील कहा से आता है? आपने स्टील एथोरिटी बनाई, मैं ज्यादा डिटेल मे जा नही सकता लेकिन मेरी समझ मे नही आता यह स्टील डिस्ट्रीब्यूशन मे घपला क्या है? हमारी एस्टीमेट्स कमेटी

ने इन सारी बातों पर गौर किया है और आपका ध्यान दिलाया है? एस्टीमेट्स कमेटी ने कहा है :

"The Committee note that the steel plants take about 45 days to issue work orders after the indents are received from the Joint Plant Committee."

ज्वाइंट प्लान्ट कमेटी में इंडेण्ट आने के बाद स्टील प्लान्ट्स 45 दिन का टाइम वर्क आर्डर इश्यु करने मे लेते है। एस्टिमट्स कमेटी ने कहा है कि यह टाइम ज्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए

"The Committee are of the view that the period of 45 days for issuing work orders is excessive."

मैं इस बात को नही समझ पाया कि आपकी इतनी कमेडिया होने के बाद आज स्माल स्केल इडस्ट्रीज की ऐसी हालत क्यों हो रही है। कमेटी ने कहा है

"The Committee are of the opinion that if the cost of steel material is high and the procedure more cumbersome, the small scale industries especially these in common production with large units are at competitive disadvantage."

स्माल स्केल इडस्ट्रीज को आपका कोटा कैसे मिलता है वह भी सर्टेन नही है। उन लोगो को आज इस कोटे से वंचित रहना पडता है। इतना ही नही, उन्होंने इस बात का भी प्वाइन्ट आउट किया है :

"The Committee would urge upon the Government to take note of the difficulties and ensure that the new procedure of distribution of steel to small sector does not result in excessive burden or hardship."

आपके जो स्टाक-यार्डस हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मैं जानना चाहता हु जो आपकी बिलेट्स और री-रोलिंग इन्डसट्री हैं उनकी क्या हालत है ? वह 116 हैं लेकिन उनके दो शिफ्ट्स भी नहीं चलते हैं । उनको अपनी जरुरत के लिए 3 मिलियन टन स्टील चाहिए लेकिन आप उनको .7 मिलियन टन स्टील भी सप्लाई नही कर सकते हैं

इसी तरह से जो स्क्रैप का मामला है उसमे भी बड़ा घपला हैं । आपको सोचना चाहिए कि जो मिले इसकी चल रही हैं उन्हे कोटा कैसे मिलता हैं । यह स्क्रैप का भी बड़ा चक्कर है । स्टाक यार्ड मे अफसर लोग बडे लोगो से मिले रहते है और अच्छे माल को स्क्रैप मे निकाल देते है । वहा से लाखों टन अच्छा माल स्क्रेप मे निकाल कर वह लोग नीलाम कर देते है। छोटे छोटे लाट्स मे नीलाम करने के बजाये बडे लाट्स मे स्क्रैप के साथ साथ अच्छे माल को भी निकाल दिया जाता है । प्रायट्री बेसिस पर इन्डस्ट्रीज को सप्लाई नही किया जाता । हमे इस बात की कोई इन्फार्मेशन नही है कि कितना परसेन्ट निकलता है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते है, कैसे वह स्टाक यार्ड मे जाता है । इसी तरह से कन्ट्रोल रेट पर जो स्टील आप देते है इन्डस्ट्रीज को वह उसको उस काम मे लाती है या नही, इसको कौन वाच करता है ? आपने किसी को कोटा दिया तो उसका सही प्रयोग होता है या नही, इसको कौन देखता है ? 1971 मे दिल्ली हाईकोर्ट मे करीब दो लाख टन स्क्रैप का मामला आया था, उस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यह आज तक मालूम नही। आपने आश्वासन दिया था कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेगे 1971 मे ही ले कन आज तक कुछ भी नही हुआ है। हाईकोर्ट का जजमेन्ट होने के बाद भी आज दो लाख टन स्क्रैप का क्या हुआ, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ? आप मुझे यह भी बतायें कि लोकल इस्टीट्यूशन्स, म्युनिसिपैलिटीज, पचायते और गावों में रहने वाले लोगों को स्टील कैसे मिल सकता है ? उनके लिए स्टील पाने का क्या रास्ता है । इसके लिए अगर कोई तरीका हो तो बतायें । इसी तरह से यह जो आपकी बिलेट्स और री-रोलिंग इन्डस्ट्रीज है उनको स्टील किस प्रकार मिलता हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं किसका

स्क्रैप निकलता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और काले बाजार मे वह कैसे आता है ? आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है उसके लिए हर कमेटी ने आपको राय दी है लेकिन फिर भी आज आपके स्टील की कन्ट्रोल प्राइस क्या है और उसका बाजार भाव क्या है यह बताये । जो आपने रीजनल आफिसर्स रखे हैं उन्होने पिछले दो सालों में कितने चालान किए हैं, कितने लोगो का प्राजीक्यूशन हुआ है और कितने लोगों को सजा मिली है ? पिछले दो साल में रिजनल कंट्रोलर ने कितने लोगों का चालान किया है, कितने मामलों की जांच पडताल की है। कौन देखता है कि इंतजाम ठीक होता है या नही। जै पी सी आपने बनाई है उसके लिए कोई गाइडलाइंज दी हैं ? यदि दी है, तो कृपा करके बताईये। प्रायोरिटीज किस आधार पर आपने तय की है ? एस्टीमेट्स कमेटी ने इस पर बडा लिखा है कि प्रायोरिटी कमेटी के लिए आपने कोई गाइडलाइन्ज नही दी है। वह अपना डिसक्रीशन इस्तेमाल करती है। आपने लिखा है कि छ महीने के लिए करेंगे एलोकेशन ? मैं जानना चाहता हूं कि एक साल के लिए क्यों नहीं ? किस तरह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का हो सकता है क्या यह भी आपने देखा है? कैसे लोगो को यह आसानी से मिल सकता है ? कितना स्क्रेप निकलता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ? स्टकायार्ड आपने कहा कहा खोले है ? क्या एक ही जगह है ? आपने दिल्ली मे एक कमेटी बनाई है। आपने आश्वासन दिया था कि जिस तरह की यहा कमेटी बनी है वैसी ही कमेटीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी जगह आप बनाएगे ? दिल्ली में यह तीन मैम्बरो की कमेटी 1971 मे बनाई गई थी। क्या उसके अच्छे नतीजे निकले है? क्या इस प्रकार की कमेटीज और जगह भी बनाई जाएगी, जयपुर, जोधपुर आदि राजस्थान के दूसरे शहरो के लिए भी बनेगी ? कैसे लोकल एरीज को स्टील मिलेगा ? अगर लोगों को यह नही मिलता है तो ब्लैक मार्किट मे कहां से आ कर अवेलेबल हो जाता है।

SHRI HARI KISHORE SINGH (Pupri): I want to know first of all the rationale behind this new policy. Why has the Government felt compelled to change the old policy and has adopted a new system of distribution? What does it expect to achieve from this new policy?

My second point is why this allotment on six-monthly basis? Does the Government think that it will result in a more rational distribution? Is there not any apprehension that this allotment on six-monthly basis may affect the production itself?

Thirdly, Shri Daga asked he question as to what will be the effect of this policy on the availability of iron and steel in the black market? I want to know whether the black-marketing m steel is going to be stopped or minimised and if minimised, to what extent or whether it will be eliminated or augmented.

Finally, I want to know the effect on small-scale industries—whether they are going to get sufficient steel for their production, especially, the village industries. In the villages we have the blacksmiths and carpenters. How they are going to get steel for their use.

Finally, what about educational institutions. The UGC has permitted construction of buildings for colleges. How are the educational institutions going to get their requirements of steel?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) लोहे का जो हमारे देश मे उत्पादन हो रहा है वह दुर्भाग्यवश काफी नही है । अब सामान काफी नही होता है तो उसको वितरण मे दिक्कत तो आ ही जाती है। इस वक्त स्केरसिटी कंडिशंज चल रही हैं। जो डिमाड है उसको सतोषजनक रीति से हम पूरा

नही कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मिनिस्ट्री को यह प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है कि वितरण जहा तक हो सके उसको संतोषजनक बनाया जाए।

हमारी नीति तो आप जानते ही हैं। प्राथमिकताओं को हमने एक फेहरिस्त बनाई है। सबसे पहले तो स्टील प्रायोरिटी कमेटी जो स्टील होता है उसको डिफेंस परपजिज के लिए देती है, जितनी उनको जरूरत होती है उसको सबसे पहले पूरा करती है। उसके बाद बिजली विभाग को हम स्टील देते है क्योकि हम समझते है कि उसके बाद वह जरूरी है और उसको मिलना चाहिए। फिर उद्योग धधो को, उन बडे-बडे उद्योग धधों को देते है जो यहा से एक्सपोर्ट करते है ताकि हम विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। हमारे ऊपर माग बहुत ज्यादा है। कुछ हद तक यह माग कृत्रिम भी होती है। वास्तविकता यह है कि स्माल स्केल इडस्ट्री की तरफ से हो या और जगह से हो माग हमारे ऊपर ज्यादा है। लगभग 13 मिलियन टन लोहे को चारो तरफ से माग हुई है हर स्तर से, वैयक्तिक क्षेत्रो से, प्रादेशिक क्षेत्रो से, बडे बडे उद्योग धधो से और हम दे सकते है पाच साढे पाच मिलियन टन। इसलिए कुछ तो दिक्कत आ ही जाती है। हम समय-समय पर अपनी योजना मे परिवर्तन भी करते रहते हैं और देखते रहते है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगो को सतोष हो।

आपने स्टाक यार्ड की बात कही है। इसमें शक नही कि स्टाक यार्ड हमारे जो पाच है वे बडी-बडी जगहो मे हैं। और भी जगह केन्द्र खोले है। और भी कई समस्याये खडी हो जाती है। यातायात की हो जाती है। गाड़िया नही मिलती हैं। जब रेल के डिब्बे नहीं मिलते है तो भी इम्बैलेंस हो जाता है। रेलों से सलाह मश्विरा करके उसको ठीक करने की कोशिश भी की जाती है। छोटे-छोटे उद्योग धंधों को कभी-कभी ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है। बडे-बडे उद्योग धधे खोले जाते हैं। उससे हमें सतोष नही होता है। एक ही तरह के काम करने वालों को कभी सीधे मिल जाती है, कभी उनको एलाटमेंट स्टाक यार्ड से हो जाती है। इसलिए कभी-कभी दामों मे विभिन्नता आ जाती है। जो कमिया दिखाई देती हैं उनको दूर करने के लिए समय समय पर कारवाई करते हैं। समय समय पर योजना में सुधार करते रहते है। पिछली मई मे कलकत्ता में एक बैठक हुई थी। उस मे हमने कुछ सुधारो की योजना बनाई है। कुछ तो हमने उसको स्वीकार कर लिया है और कुछ नही किया है। अभी तक सरकार ने उस पर पूरा निर्णय नही लिया है। हमारा प्रयत्न यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाये छोटे बनाने वालों को दे सके। प्रादेशिक सरकारो के साथ तारतम्य स्थापित करके ही ऐसा हो सकता है। जो भी हम दे सकते है दे और ठीक से वे उसको बाटे। हमारा अनुभव यह है कि जो माग आती है प्रादेशिक सरकारों की तरफ से, उनके ऊपर जो माग आती है उसको वे हमारे ऊपर डाल देते है पूरी की पूरी को। उसको हम पूरी नही कर पाते है। कभी कभी इधर उधर गडबडी भी हो जाती है। हमारी प्रार्थना प्रादेशिक सरकारो से यह है कि वे अपनी माग को इस तरह रखें ताकि जो कमी है उस कमी के अन्दर इम्बैलेंस न हो, लोगो के साथ अन्याय न हो।

18 hrs.

श्री डागा ने कहा है कि हमारे रिजनल डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में गड़बडी होती है और चालान नहीं होते हैं। ऐसी बात नही है। बहुत चालान होते हैं। बहुत से लोग पकडे जाते हैं, बहुतों के लाइसेंस बन्द किये जाते है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थिति है, जिस में कोई न कोई सामने आ ही जाता है। हमने सैकड़ों की तादाद में लोगों को देना बन्द किया है, चालान किये हैं, मुकदमे चलाये है और कानून के मुताबिक हर तरह की सजा दी है। रिजनल स्टील कंट्रोलर का काम आम तौर पर अच्छा हुआ है, जिस की वजह से डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में उन्नति हुई है। लेकिन

मैं यह तस्लीम करता हू कि वह सतोषजनक नही है। उस का खास कारण यह है कि हम पूरा उत्पादन नही कर पाते है।

स्माल-स्केल इडस्ट्रीज को जो क्वोटा मिलता है, वह भी हम सीधा देते हैं। अगर वे रेक के रेक ले जाना चाहते हैं तो हम पूरा रेक देते हैं। अगर उन्हे कम चाहिए, तो आस-पास की जगह से उन को मिलता है। इसमे दामो मे फर्क हो जाता है। लेकिन उनको दाम की चिन्ता नही होती है। उनको लोहा चाहिए, और वे किसी तरीके से प्राप्त कर लेते है। हम इसमे सुधार करना चाहते है।

जो बिलेट चाहते है, उन को पूरा नही मिल पाता है, क्योकि जितने बिलेट की जरूरत होती है, वह हम बना नही पाते है। इस समय आयरन ओर और कोयले वगैरह की जो दिक्कते है, जिनका श्री डागा ने जिक्र किया है, जब वे दूर हो जायेगी, तो हम बिलेट के उत्पादन मे वृद्धि करेंगे। बिलट कम मिलता है, तो एलोकेशन हो जाता है कि बिलेट का सामान किस को दिया जाय। उसमे इधर-उधर कही गडबडी न होती हो, मैं ऐसा नही कह सकता हु। जिस तरह सतोषजनक रीति से वह मिलना चाहिए, वह बहुधा नही मिल पाता है। इसी लिए हम बराबर सतर्क रहते है और कोशिश करते है कि हम अपनी योजना मे सुधार करते रहे। पिछले जमाने मे हम बार-बार बैठे हैं, हम ने विचार किया है और कुछ सुधार हुआ है, चाहे वह पिग आयरन का वितरण हो और चाहे फिनिश्ड स्टील का।

बड़ी बड़ी इमारतो के लिए जो लोहा पा जाते हैं, वह हेर-फेर मे बदना है। माननीय सदस्यो को गवर्नमेंट की पालिसी मालूम हो गई होगी कि हम बडी-बडी इमारतो के खिलाफ है। सीमेंट हमारे पास नही हैं और लोहा भी पर्याप्त मात्रा मे नही हैं। जितना लोहा हम बाहर भेज सकते हैं, उस को भेज कर हम फारेन एक्सचेंज पैदा करना चाहते है। इसलिए हम ने यह छूट दे दी है कि जो भी बार्ज और एगल्ज आदि लोहा बाहर भेजना चाहता है, वह भेजे। उस के लिए बहुत माग आई है और वह काम शीघ्रता से हो रहा है।

हमे सतोष है कि निर्यात के लिए हमारा जो प्रबन्ध हैं, वह ठीक तरह से चलने वाला है। अगर हम उत्पादन बढा सकेंगे, तो हम बाहर से ज्यादा पैसा भी कमा सकेंगे, दामो पर भी काबू कर सकेंगे और वितरण भी कर सकेंगे।

स्क्रैप की कमी है। दुनिया भर में स्क्रैप की कमी है। स्क्रैप का दाम बहुत बढ गया है। बाहर से स्क्रैप मगाने मे दिक्कत हो रही है, क्योकि वे शर्तें हम स्वीकार नही कर पा रहे हैं। इस लिए हमारे यहा जो स्क्रैप है, उस के लिए खीचा खींची रहती है। कलकत्ता और बम्बई वगैरह मे स्क्रैप का एकत्रीकरण होता है। वहा स्क्रैप को प्रासेस करने के कारखाने है। वे बनाते है और बेचते हैं। कुछ पर हमारा कट्रोल है और कुछ पर नही है। हम चाहते है कि स्क्रैप से बनाये हुए लोहे के वितरण पर हमारा कट्रोल हो। हम उस को बढाना चाहते है।

स्क्रप की कमी के कारण नयी टैकनालोजी का प्रवेश होने वाला हैं। वह एक लम्बी कहानी है जिस के बारे मे मैं फिर कभी सदन को बताऊगा। हम उस पर विचार कर रहे है।

लोहे के कारखाने एक ही जगह बन जाते है। हम उस का विकेन्द्रीकरण करना चाहते है। उसकी टैकनालोजी और इकानोमिक्स का अध्ययन किया जा रहा है। हमे आशा है कि हम स्टील के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण कर के स्टील का उत्पादन शीघ्रता से बढा सकेंगे। हम ने कोयले से स्पाज आयरन बनाने की तरफ काफी प्रगति की हैं। हमारे यहा कोयले से अच्छा स्पाज आयरन बन सकेगा, जिस को हम छोटी-छोटी भट्टियो में बना सकते हैं। इस के बारे मे हमने बडी मेहनत की है और हमारी कोशिश हो रही हैं।

An HON. MEMBER: Have you seen the criticism regarding that?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने जो ब्यान सामने रखा है, उस के बारे में कोई सीरियस, लैजिटिमेट और वैलिड क्रिटिसिज्म अभी तक अखबारों में नहीं आई है । जब कोई नई योजना देश के सामने आती है, तो अक्सर कुछ लोग उस का विरोध मशीन में कर दिया करते है, कुछ सिनिकली कर देते है और कुछ समझ-बूझ कर भी करते है । मेरा निश्चित मत है कि अपनी पालिसी और फेमवर्क में रह कर हम स्टील इंडस्ट्री का जितना भी विकेन्द्रीकरण कर सकें, वह करें । मुझे कोई सन्देह नहीं है कि वह टैकनीक हम को मालूम हो रही है ।

गुजरात में गैस से स्पाज आयरन बनने वाला है । हमारे देश में अगरतला में बहुत गैस मिली है । हम उस से बहुत अधिक मात्रा में स्पाज आयरन बना सकते है । हमारे यहां लो ग्रेड क्वालिटी का कोयला बहुत अधिक मात्रा में है । वह स्पाज आयरन बनाने के लिए उपयुक्त है । वह स्क्रैप को बिल्कुल रीप्लेस कर देगा। लेकिन वह आज नहीं, दो चार पांच दस साल में बनने वाली चीज है । मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्टील के उत्पादन में वृद्धि कर के वितरण की समस्या को संतोषजनक ढंग से हल कर सकते है । हम बीच बीच में कमेटियों के द्वारा मिला करेंगे ।

स्टेट गवर्नमेंट्स के सहयोग से हम पंचायतों, म्यूनिसिपल कमेटियों और छोटे मकान बनाने वालों को प्राथमिकता देंगे । हमारी पालिसी यह है कि जहां तक हो सके, हम ऐसे लोगों को, जिनको थोड़े बहुत लोहे की जरूरत होती है, लोहा दे सकें ।

श्री भक्तचन्द डागा : दिल्ली ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे दिल्ली का मालूम नहीं है । मैं मालूम करूंगा ।

श्री भक्तचन्द डागा : पब्लिक सैक्टर में जो स्क्रैप होता है, वह कैसे डिसपोज आफ होता है ? वहां सर्विस वाले सारा गोलमाल कर देते है ।

SHRI K. D. MALAVIYA: Integrated steel mills produce a lot of scrap and rejects. They are auctioned. The system of auctioneering may be satisfactory or may not be satisfactory so we had a new look and tried to improve upon the distribution. Right now we are think of how to now we are thingnk of how to improve the auction ...

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मिलाई में स्क्रैप के नाम पर अच्छा लोहा बेचा गया है । देश के प्राय. सभी समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था ।

श्री के० डी० मालवीय : अगर माननीय सदस्य किसी विशेष बात की तरफ मेरा ध्यान दिलायेंगे, तो मैं आश्वासन देता हूं कि इस बात की पूरी पूरी जांच करूंगा कि अच्छा लोहा स्क्रैप के नाम पर बेचा जाता है । लेकिन लेने वाले लोग आपस में मिल कर कोशिश करते हैं कि सस्ते में ले । उस योजना का हम ने संशोधन किया है और हम समझते है कि जो गलतियां हो रही हैं, या बेईमानी होती है, इन से हम उन को ज्यादा से ज्यादा रोक सकेंगे और हम ने रोका भी है

In totality we have affected improvement both in the auctioneering of the scrap that is available in the steel mills and also in the distribution system but I again submit to the House that the defects in the distribution system .

MR CHAIRMAN: Mr. Malaviya, one point was raised by Mr. Daga and others that steel is available to those who are utilising it for non-priority and ostentatious constructions. How do they get that and can you regulate it?

SHRI K. D. MALAVIYA: We are trying our best to regulate it in our billet rolling mills in a proper way

but the fact is that we have to regulate the priority on the basis of which steel is allotted. Some industries, both big and small, may be responsible for diverting a part of their steel in the market where a very good price attracts the suppliers and they get it. They manage to get it. It is an inbuilt evil in society. . . .

So, from that point of view, Government have now decided to restrict the construction of buildings from the point of view of restricting the supply of steel and also cement. I hope that this scheme of Government to put such restrictions will end in a not unbalanced distribution.

All that I can is that we shall try to improve the situation The situation has improved, and in the next few months, our emphasis will be to satisfy as far as it is possible the needs of the small consumers and also to streamline the distribution system by creatmg more distribution centres.

There is an imbalance in prices also Those who get the steel directly from the steel mills have to pay less, while those who get it from the stockyards have to pay a little more because of the expenditure that is involved in the stockyard organisation. There also, we are trying to see how best to minimise the difference or equalise the price system. I think we may have to look into it again and reduce or completely eliminate the differential in price so far as supplies from the steel mills and other centres are concerned.

With all these precautions, I hope that the distribution system will improve and our steel production will also improve

श्री मूलचंद डागा : देखिए जो आप का उत्तर है उस के लिए तो मैं आप को धन्यवाद देता हूं आप ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया लेकिन मेरे किसी स्पेसिफिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैंने यह कहा था कि आप ने स्टील कंट्रोल आर्डर के तहत कितने लोगों का चालान किया, एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अंतर्गत कितने लोगों पर मुकदमे चलाए, कितनों को सजा हुई, कितने जेल चले गए दो साल में तीन साल में एक तो बताइए । फिर मैं ने यह पढ़ा था :

"The Committee note that at present the stockyard remuneration ranges from Rs. 60 to 380 per tonne on various items of steel sold through stockyards .. The Committee would, therefore recommend that Government should review carefully the margin of remuneration allowed for sales from stockyards so as to reduce it to the minimum in respect of categories of steel which are used mostly by the small-scale industries.

सभापति महोदय : उस का जवाब तो उन्होंने दिया है, आप ने शायद सुना नहीं कि वह रिड्यूस करना चाहते हैं वह जो डिफरेंस हैं स्टाक यार्ड में जो मिलने वाला है और डायरेक्टर मिलने वाला है, उसके बारे में तो उन्होंने बताया ।

श्री मूलचंद डागा : वह इतना सैटप सैट कैसे रिड्यूस हो जायेगा ? क्या होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य बैठ जायें मैं समझ गया । आप ने यह कहा कि दोनों के दामों में फर्क है, उसे कम करना चाहिए । स्टाक यार्ड जब रहेगा तो वहां पर जमीन ली जायेगी, नौकर रखे जाएंगे तो कुछ तो दाम में फर्क रहेगा । अब उस का दाम कौन देगा ? इसलिए इस पर विचार कर रहे है कि दोनों के दामों में किस तरह से तारतम्य मिलाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि दो सौ तीन सौ रुपये के करीब दाम में फर्क पड़ता है । तो उस को कम करने का प्रयत्न करेंगे, देखेंगे कि कितना कम हो सकता है । इस सारी वितरण की प्रणाली में कितना अंतर ला सकते है ताकि ज्यादा फर्क दामों में न पड़े उस

[श्री के० डी० मालवीय]

को देखेंगे। लेकिन दो सौ तीन सौ रुपया लोगों को देने में कोई एतराज नहीं है।

दूसरी जो आप ने चालान की बात कही हम लोगों ने सैकड़ों आदमियों के चालान किए है । उस में हम इतना ही कर सकते है कि उन का वितरण का अधिकार छीन सकते है तीन साल से पांच साल के बीच में हम उन के अधिकार छीन लेते है।——(व्यवधान) अब सजा देना तो मेरे हाथ में नहीं है। वह तो मुकदमा चलने के बाद होना है।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है । सजा क्यों नहीं उन को हो सकती ?

दूसरे आप के रीजनल कंट्रोलर जो है वे उन से मिल जाते है ।

श्री के० डी० मालवीय सब अफसर खराब है यह भी मै नहीं मानता । लेकिन यह मै कह सकता हूं कि उन के लाइसेंस हम ले लेते हैं और उन्हें बांटने नहीं देते है । एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट मे मुकदमा भी चलाया जाता है । अब उन को सजा होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, यह तो मेरे पास सूचना इस समय नहीं है । अगर आप को सन्तुष्टि इस बात मे हो तो जो मेरे पास सूचना होगी वह मै दे दूगा । लेकिन मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि 400 या 500 कितने पकड़े गए, कितनो पर मुकदमे चल रहे है यह मै माननीय सदस्य को दे दूगा । मै समझता हू कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो हमारे है उन से सतोषजनक काम हो रहा है । लेकिन जो निहित दिक्कतें है उन के अंदर उन की तरफ मैंने इशारा कर दिया और वह हमारे कंट्रोल के अंदर तभी आ सकती है जब कि उत्पादन की वृद्धि हो ।

MR CHAIRMAN The House stands adjourned till 11 A M tomorrow

18 15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, August 24, 1974/Bhadra 2, 1896 (Saka)

GMGIPND—I—1845 LS—JC 2993—27-9-74—978